चर्चा होने की सम्भावना है, उन लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे, जो आज एक ग्लास शुद्ध पानी के लिए तरस रहे हैं ?

श्री लालकृष्ण अडवानी : मैं बता चुका हूं कि दूरदर्शन विस्तार केवल इस आधार पर होगा कि उस के द्वारा मनोरंजन नहीं, बल्कि शिक्षा हो, उस के द्वारा विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया जाये और स्वास्थ्य आदि की शिक्षा दी जाये । दूरदर्शन का विस्तार इस उद्देश्य से ही होगा, मनोरंजन की दृष्टि से नहीं होगा ।

SHRI A. C. GEORGE: Karnataka offered hospitality to the hon. Minister for 19 months and they are getting at least a satellite or a relaying centre. We do not have that privilege in Kerala; we have been denied even that. Whenever there is a proposal about television centre, the usual plea put forward by the Finance Ministry or the Information Ministry or by any spokesman of the Government is 'financial constraints'. Now the very concept of television broadcasting is changing and it is being considered commercially viable. So, instead of always putting forward the plea of financial restraints, why should not the Broadcasting Minister take a new look at the subject of television and come forward with a proposal whereby it can be made—commercially viable and why should it not be extended to states in the extreme south, like Kerala? I am sure he has much sympathy for the southern States then why should he not think of putting up commercially viable television centres in the south also?

SHRI L. K. ADVANI: I have been listening to two contradictory viewpoints. But, as the Government has stated, if you think purely in terms of commercially viability, then the bias will be in favour of urban-based entertainment: it is bound to be so. But if you think in terms of harnessing the T.V. for developmental purposes, for educational purposes, for health purposes and for purposes of agriculture, then the approach has to be entirely different and this is the approach that Government has adopted. I would like to point out that there is no question of any geographical bias this way or that way: it is our attempt to cover the whole country as far as possible and to have the maximum possible coverage, subject to financial constraints.

Dr. KARAN SINGH: Apart from the entertainment and educational aspects, Television has also a very important political impact, particularly in the border States. So, particularly in regard to these States where Pakistan Television is very easily available and very powerful, there was a proposal for setting up television stations in places like Srinagar, Amritsar, etc. But I am surprised to learn from the list read out that the proposal for a relay station in Jammu seems to have been dropped. I would urge that at least in States like that, where you can see Pakistan television the whole day, top priority should be given for setting up either original stations or relay stations.

SHRI L. K. ADVANI: This is a suggestion for action and I will have it in mind. But, as I have said, so many things are desirable but may not be feasible.

श्री वीरेन्द्र प्रसाद : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नालन्दा जिले में राजगिर जो अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति की जगह है जहां बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर के आते रहते हैं वहां क्या टेलिविजन केन्द्र खोलने की योजना है ?

श्री लालकृष्ण अडवानी : इस समय उस की योजना नहीं है ।

SHORT NOTICE QUESTION

Cowting bridge of Rajghat bridge on Madhaya Pradesh and Rajasthan border between Agra-Bombay Highway

S.N.Q. 22. SHRI CHHABIRAM ARGAL: Will the Minister of SHIP-

PING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Cowting bridge of Rajghat bridge on Madhya Pradesh and Rajasthan border between Agra-Bombay Highway has given way and steamers service is also not being operated; and

(b) if so, whether road traffic has been dislocated as a result thereof and whether Government will arrange urgently for additional railway coaches to facilitate movement of traffic?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) and (b). Presumably, the Hon'ble Member has in mind the Pontoon bridge on river Chambal on Agra-Bombay, National Highway 3 at Madhya Pradesh-Rajasthan border, set up for the fair-weather usage close to the National Highway bridge, which was damaged sometime back and is already being reconstructed. The Pontoon bridge was removed on 27-6-1977 for the monsoon period as usual. After the dismantling of the bridge, ferry service with ramped power launches is available and is suspended only when the river is in flood. When that happens, the traffic unavoidably takes to alternative road routes for short periods.

श्री छविराम अर्गल : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा पर राजघाट पुल का ब्रिज 1959 में बना था और 1960 में इस पर आवागमन चालू हुआ । 13 साल के बाद 1 मार्च, 1973 को यह पुल टूट गया । क्या इस पुल के बारे में 8 मई, 1973 को एक कमेटी बनाई गई थी ? यदि हां तो उसकी क्या रिपोर्ट आई है ?

मैं सरकार का ध्यान एक बात की ओर और भी आकर्षित करना चाहता हूं कि पहले जब उधर से, प्रतिपक्ष की ओर से, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय तथा श्री हुकम चन्द कछवाय ने इस बात के बारे में चिन्ता व्यक्त की थी और कहा था कि राजघाट पुल टूट जाने से जनता को बहुत कठिनाई हो रही है, आवागमन में बहुत तकलीफ हो रही है इसको बनाया जाये तो डा० पांडेय जी के 26 जून, 1973 को एक प्रश्न सं० 488 के उत्तर में बताया गया था कि पुल रिपयर होगा, तो दो वर्ष की अवधि में रीकन्डक्ट होगा तो 3 वर्ष की अवधि में इसको बना दिया जायेगा । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस पुल को बनाने में कितना समय लगेगा और कब तक यह बनकर तैयार हो जायेगा जिससे कि वहां पर आवागमन प्रारम्भ हो सके ?

SHRI MORARJI DESAI: The Government of India had appointed an Enquiry Committee in May, 1973 to enquire into the causes of collapse of the Chambal N.H. 3 bridge and to suggest measures for reconstruction of the bridge. The Committee gave its findings and recommended restoration of the existing bridge. Accordingly, tenders were called for and a contract was given in November, 1975 for a lumpsum cost of Rs. 217 lakhs. Several foundations have been completed, but some are still remaining. The bridge is expected to be completed by December, 1978 and the total cost is likely to be Rs. 297 lakhs.

श्री छविराम अर्गल: क्या यह सही है कि 27-6-77 को इस काउटिंग ब्रिज के टूट जाने से बम्बई से दिल्ली जाने वाले लोग या वाहन इन्दौर, कोटा, जयपुर होते हुए दिल्ली जा रहे हैं, सीकर, कोटा, जयपुर होते हुए दिल्ली के लिए आवागमन हो रहा है और भिण्ड इटावा से दिल्ली होकर जाना पड़ता है । इस प्रकार से यह मार्ग अवरुद्ध हो गया है । तो मैं जानना चाहता हूं कि जो

वहां रेल सेवा चालू है, जो तेज गाड़ियां चलती हैं वह ग्वालियर, मुरैना रुकती नहीं हैं, क्या उन गाड़ियों को वहां पर रोकने की व्यवस्था की जायेगी जिससे कि यात्री सफर कर सकें ? इसके साथ ही क्या माल ढोने के लिए अतिरिक्त डिब्बों तथा पसेंजर्स के लिए सेकेण्ड क्लास के डिब्बों और अतिरिक्त सीटों के कोटा की व्यवस्था भी की जायेगी ?

श्री मोरारजी देसाई : रेल मंत्रालय से पूछा गया था, उन्होंने कहा यह सम्भव नहीं है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : उपाध्यक्ष महोदय, 1959 में यह पुल बना और 1960 में चालू हुआ क्या जिस ठेकेदार ने इस पुल को बनाया था उसके साथ कोई शर्तें थीं कि कितने दिनों तक यह पुल टूटेगा नहीं ? यदि हां, और उस समय से पहले पुल टूट गया तो उस ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

दूसरी बात यह है कि प्रधान मंत्री जी ने कहा कि दिसम्बर, 1978 तक इस पुल का काम पूरा हो जायेगा लेकिन अभी वहां पर किसी प्रकार का काम नहीं चल रहा है और इस रिपोर्ट में बहुत सी तथ्यहीन बातें दी गई हैं तो क्या उनकी आप अलग से जांच करवायेंगे ? आज वहां लोगों को जो परेशानियां हैं वह इतनी भयंकर हैं कि 15-15 दिन तक लोग ट्रक और बसेज लेकर पड़े रहते हैं, उन्हें जाने के लिए कोई मार्ग नहीं मिलता है । जिन मार्गों से उनको जाना पड़ता है उन मार्गों की क्षमता इतनी नहीं है कि इतने ज्यादा लोड को ले सकें । उन मार्गों की हालत भी बहुत खराब हो गई है । ऐसी स्थिति में आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं जिससे यह मार्ग जल्दी से चालू हो सके और जो छोटे मार्ग हैं उनको अधिक लोड न उठाना पड़े और जो लोगों को 10-15 दिन रुकना पड़ता है वह कठिनाई दूर हो सके ?

श्री मोरारजी देसाई : जल्दी चलाने की कोशिश हो रही है । मैंने कहा कि दिसम्बर, 1978 तक पूरा हो जायेगा । 15 दिन तक किसी को रुकना पड़ा, यह तो मुझे मालूम नहीं है । ऐसी शिकायत मेरे पास भेजें तो मैं जरूर जांच करूंगा ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : जिस ठेकेदार ने पुल बनाया था उससे कोई शर्त थी ?

श्री मोरारजी देसाई : ऐसी कोई शर्त नहीं होती है ।

श्री रघुबीर सिंह मछण्ड : इस पुल के टूटने का कारण क्या है ? इसमें सरकार की गलती हुई या ठेकेदार की और अगर ठेकेदार की गलती है तो उसके खिलाफ सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए ?

श्री मोरारजी देसाई : गल्ती तो कुदरत की थी । सिर्फ कुदरत की नहीं, समझने वालों की थी । दोनों की थी ।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय: मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जब यह पुल बना, उसी समय इस में इस प्रकार की खामियां थीं ? जिस समय कोई पुल बनाया जाता है तो उस की कोई अवधि होती है कि 50 साल या 25 साल तक चलेगा, क्या जिस अवधि के लिये यह पुल बना था, उस के पूरा होने के पहले ही टूट गया ? इस पुल के टूट जाने से सारा यातायात अवरुद्ध हो गया है, जिस के कारण बहुत परेशानी हो रही है । दूसरे मार्गों पर भी भारी यातायात है और वहां का यातायात कई दिन तक वर्षा में रुका रहता है । पहले कहा गया था कि यदि

इसको रीकस्ट्रक्ट नहीं करना पड़ा तो 3 सालों में पूरा हो जाएगा। मैं प्रधान मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि आपने उन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही की है, जिन्होंने इस प्रकार के डिफेक्टिव पुल का निर्माण किया या जिनके जिम्मे यह निर्माण कार्य था ?

श्री मोरारजी देसाई : यह इनफर्मेशन इस वक्त मेरे पासनही है, लेकिन मैं इसके बारे में जरूर तपास करूंगा और ऐसा हुआ है तो कदम उठाऊंगा। लेकिन नया ब्रिज 1978 तक जरूर पूरा होगा ऐसा मुझे विश्वास दिलाया गया है ?

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Assistance for setting up paper Units

*548. SHRI M. RAM GOPAL REDDY: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Paper industry in the country has urged for assistance to expand the present production and for setting up more paper units in the country; and

(b) if so, the reaction of Government thereon?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) and (b). Government have been receiving from time to time, various suggestions from individuals and firms connected with the Paper Industry on improvement of productivity and incentives for further growth. Government have been taking these into account while considering measures to increase the production of paper.

Levy imposed on Films

*549. SHRI NIHAR LASKAR:

SHRI M. KALYANA-SUNDARAM:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether a delegation of film producers met him and placed before him the difficulties in regard to levy imposed by the Finance Minister;

(b) if so, whether the delegation had also met the Finance Minister and urged him to revise the levy; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) and (b). Yes, Sir.

(c) The Minister of Finance has already announced certain modifications in regard to the levy of Excise Duty on films, which it is hoped, will go a long way in mitigating the grievences of of the film industry.

Agitation by All India Defence Employees Federation

*550. SHRI K. A. RAJAN: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether All India Defence Employees Federation has decided to start a country-wide agitation to press their demands; and

(b) if so, what are their demands and Government's response thereto?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM): (a) No formal notice has been received in the Ministry of Defence in regard to the proposed agitation by the All India Defence Employees Federation. A news item published in the Defence